GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *252
ANSWERED ON - 11.08.2023

LACK OF ADEQUATE FOOD PROCESSING UNITS

***252 SHRI M. MOHAMED ABDULLA:**

Will the Minister of *Food Processing Industries* be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that about 40 per cent of perishable food is wasted in the country due to lack of adequate food processing units, cold chain and storage despite significant growth in the sector; and
- (b) if so, the steps taken by Government to resolve it?

ANSWER

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
(SHRI PASHUPATI KUMAR PARAS)

(a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO PART (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *252 TO BE ANSWERED ON 11.08.2023 REGARDING “LACK OF ADEQUATE FOOD PROCESSING UNITS”

(a) & (b): As per studies conducted by Indian Council for Agricultural Research – Central Institute of Post-Harvest Engineering & Technology (ICAR-CIPHET), 2015 and NABARD Consultancy Service Pvt. Ltd (NABCONS), 2022, the estimated percentage of Harvest and Post Harvest loss of perishable food is as follows:

Commodities (Perishables)	Estimated Percentage Loss	
	As per ICAR-CIPHET study (2015)	As per NABCONS study (2022)
Fruits	6.70-15.88	6.02-15.05
Vegetables	4.58-12.44	4.87-11.61
Milk	0.92	0.87
Fisheries(Marine)	10.52	8.76
Fisheries(Inland)	5.23	4.86

The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) supports the creation and expansion of the processing/preservation capacity through implementation of various schemes to reduce post-harvest losses and create higher value-addition. The schemes are as follows:

- (i) Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY)
- (ii) PM-Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME)
- (iii) Production Linked Incentive (PLI) scheme

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *252
11.08.2023 को उत्तर देने के लिए

पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव

***252 श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीतागारों और भंडारण की कमी के कारण देश में लगभग 40 प्रतिशत खराब हो जाने वाले भोज्य पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

“पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव” के बारे में 11 अगस्त 2023 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *252 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट – हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस) वर्ष 2022, द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, शीघ्र खराब होने वाली फसल और फसल की कटाई के बाद के नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार है:

वस्तु (शीघ्र खराब होने वाले)	अनुमानित प्रतिशत हानि	
	आईसीएआर (सिफेट) अध्ययन वर्ष (2015) के अनुसार	एनएबीसीओएनएस(नैबकोंस) अध्ययन वर्ष (2022) के अनुसार
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्जियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (समुद्री मत्स्यकी)	10.52	8.76
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (खा.प्र.उ.मं.) फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और उच्च मूल्य-वर्धन का सृजन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता सृजन और विस्तार का समर्थन करता है। योजनाएँ निम्नलिखित हैं :

- i. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)
- ii. प्रधानमंत्री -सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई)
- iii. उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

MR. CHAIRMAN: Shri M. Mohamed Abdulla. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister.
...*(Interruptions)*...

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Q.No.253. ...*(Interruptions)*... Dr. Amar Patnaik. ...*(Interruptions)*...